









उत्तराखण्ड में पर्यटन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं : सीएम

ऊर्जा संरक्षण को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी को सदैव प्रयास करने होंगे। ऊर्जा संरक्षण हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना जरूरी है। ज्ञान एवं विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए भी अनेक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।



इन तकनीक के साथ ही हम बिजली का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करें, इसे सबको अपनी आदतों में लाना होगा। यह हमारे छोटे-छोटे प्रयासों से ही संभव है। राज्य सरकार ईकोलॉजी एवं ईकोनॉमी में संतुलन बनाये रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन एवं ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की अवधारणा में पर्यटन

एवं ऊर्जा आर्थिकी के मूल आधार थे, इस पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऊर्जा संरक्षण दिवस अवसर पर कौलागढ़ रोड स्थित ओएनजीसी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण एवं ओएनजीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित 2023 के टेबल कलेण्डर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। राज्य में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य को जलद एनओसी मिले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का सतत विकास, सतत ऊर्जा से ही संभव है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए टीएचडीसी के साथ एक संयुक्त उपक्रम पर कार्य भी किये जा रहे हैं। राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा उत्पादन के साथ ही ऊर्जा की बचत पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि हम ऊर्जा की

पहाड़ों से पलायन गंभीर मुद्दा, अधिकारी ईमानदारी से करें सर्वेक्षण कार्य

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिलाधिकारी ने कहा कि पालयन एक गम्भीर विषय है जो कि आगे चलकर पहाड़ के भविष्य को तय करेगा, इसलिए पलायन से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्यों में अधिकारी अपने विवेक व तकनीकी दक्षता का पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर रिपोर्ट तैयार करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 50 प्रतिशत से अधिक पलायन कर चुके जनपद के 91 गांवों में जाकर पलायन के कारण का सर्वेक्षण कार्य ईमानदारी के साथ पूरा करें। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से आच्छादित 11 ग्राम/तोका/ मजरो में जनसांख्यिकीय एवं मूलभूत सुविधाओं के सर्वेक्षण को लेकर



डीएम डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सर्वेक्षण फार्म पलायन के पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को

प्रदेश के पलायन सम्बन्धि आंकड़ों में जनपद पौड़ी का 6.8 प्रतिशत योगदान है। पलायन के इस आंकड़े में 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि जनपद में एक हजार लोगों में से 3.44 लोग पलायन कर रहे हैं। जबकि आयोग के गठन के बाद स्थायी पलायन पांच प्रतिशत तक रुका है। बैठक में डीडीओ पुष्पेन्द्र चौहान, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चन्द्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलाने, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेन्द्र चौधरी, डीपीआरओ जितेन्द्र कुमार, जिला सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से आच्छादित 91 गांवों की मैपिंग करवाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में पलायन रोकथाम आयोग के सदस्य ने बताया कि

जनता के हित में कार्य कर रही सरकार : धन सिंह



काबौना मंत्री डॉ. धन सिंह रावत श्रीनगर अस्पताल में जलाशय निर्माण का शिलान्यास करते हुए।

जलाशय निर्माण व पंप सेट अधिष्ठापन कार्य का किया शिलान्यास जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर योजनाओं का शिलान्यास

किया। उन्होंने श्रीकोट अस्पताल में 350 केएल जलाशय निर्माण व 02 नग पंप सेट अधिष्ठापन कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान काबौना मंत्री ने कहा कि सरकार निरंतर रूप से जनता के हित में कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने दृंगरी पन्थ पंचायत भवन (सामान्य) व पंचायत भवन (अनुसूचित

जाति) का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गांव में पंचायत भवनों से ग्रामीणों को काफी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने श्रीकोट अस्पताल में 350 केएल जलाशय निर्माण का शिलान्यास के पश्चात अस्पताल के छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से वार्ता कर सुविधाओं से संबंधित जानकारी

रुद्रप्रयाग में कार्डियक केयर यूनिट शुरू



जयन्त प्रतिनिधि। रुद्रप्रयाग : जनपद वासियों के लिए खुशी की खबर है कि जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नया मुकाम हासिल किया है। चिकित्सालय में आने वाले हृदय रोगियों के लिए पांच बेड का

कार्डियक केयर यूनिट का शुभारंभ विधायक भरत सिंह चौधरी एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जिला चिकित्सालय को जल्द ही सीटी स्कैन और दो डायलसिस की मशीनें भी उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर

विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जनपद के लिए खुशी की बात है कि लंबे समय से जो कार्डियक केयर चिकित्सा सुविधा का इंतजार कर रहे थे वह सुविधा अब जिला चिकित्सालय में शुरू हो गई है। जिसमें पांच बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कार्डेंट की सुविधा

बचत करते हैं, तो वह भी ऊर्जा के उत्पादन के बराबर है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जागरूकता के लिए स्कूल के बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे विभिन्न जानकारियों को व्यावहारिकता में लाने के साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करते हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करने में इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। इस अवसर पर अपर सचिव ऊर्जा डॉ. अहमद इकबाल, कार्यकारी निदेशक ओएनजीसी आईसाई राम, उप महाप्रबंधक ओएनजीसी श्रीमती आरएस नारायनी, एमडी यूजेवीएनएल श्रीमती संदीप सिंघल आदि उपस्थित थे।

एमवी एक्ट में किए 21 चालान, लगाया 63 हजार 7 सौ का जुर्माना



जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और परिवहन विभाग द्वारा पौड़ी बुआखाल मोटर मार्ग पर संयुक्त रूप से चैकिंग अभियान चलाया गया। संयुक्त चैकिंग अभियान के दौरान एमवी

एक्ट के अंतर्गत 21 चालान कर 63 हजार 7 सौ 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। उप जिलाधिकारी सदर आकाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पौड़ी बुआखाल मोटर मार्ग पर चैकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना लाइसेंस, क्षमता से अधिक यात्री सहित अन्य मामलों में 21 चालान किए गये। उन्होंने वाहन चालकों

सम्बन्ध विच्छेद

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा पुत्र अजय रावत पुत्र गणेश रावत शपथी एवं शपथी की पत्नी ज्योति रावत के कहने सुनने में नहीं है। जिसके कारण मैं एवं मेरी पत्नी अपने पुत्र अजय रावत से संबंध विच्छेद करते हैं तथा अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से वेदखल करते हैं। उसका अब शपथी एवं शपथी की पत्नी की चल एवं अचल सम्पत्ति पर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यदि शपथी का पुत्र किसी से किसी भी प्रकार लेन-देन एवं अन्य कोई भी कार्य करता है तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार होगा।

गणेश रावत पुत्र स्व0 भगत सिंह रावत निवासी रमेश नगर वाई नंबर 15, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, (0744/25) उत्तराखण्ड

संबंध विच्छेद

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र शिव सिंह व पुत्रवधु धनेश्वरी देवी मेरे कहने सुनने में नहीं है। जिसके कारण मैं अपने पुत्र शिव सिंह एवं पुत्रवधु धनेश्वरी देवी से संबंध विच्छेद करती हूँ तथा अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से वेदखल करती हूँ। यदि भविष्य में मेरे पुत्र शिव सिंह एवं पुत्रवधु धनेश्वरी देवी द्वारा किसी भी प्रकार के कृत्य व लेन-देन किया जाता है तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, मैं उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य व लेन-देन के लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगी।

सावित्री देवी पति सुरेन्द्र सिंह नेगी निवासी वालागज, पोस्ट कलालघाटी, पट्टी हल्दुखता, तहसील कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, (0745/25) उत्तराखण्ड

Advertisement for 'Uttarakhand Power Corporation Ltd' regarding electricity bill payment. It includes details about the company, contact information, and a table listing various electricity supply points with their respective tariffs and terms.

Advertisement for 'Pradhan Mantri Kisan Bima Yojana' (PM-KISAN). It features a large image of Prime Minister Narendra Modi and text explaining the scheme's benefits, including a 75% increase in the number of beneficiaries and a 1.25 lakh crore increase in insurance coverage. It also mentions a 5.5 lakh crore increase in the number of beneficiaries and a 1.25 lakh crore increase in insurance coverage. The ad encourages farmers to avail themselves of the scheme by 15th December 2022.





